

## 50 से अधिक वस्त्र उत्पादों पर आयात शुल्क हुआ दोगुना

### चर्चा में क्यों?

घरेलू वनिरिमाण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने जैकेट, सूट और कालीन जैसे 50 से अधिक कपड़ा उत्पादों पर आयात शुल्क को 20% तक बढ़ा दिया है।

### प्रमुख बढि

- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड ने अधिकांश वस्त्र उत्पादों पर आयात शुल्क को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है।
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (Central Board of indirect Taxes and Custom-CBIC) द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, कोट, पैट, जैकेट तथा महिलाओं के वस्त्रों पर आयात शुल्क को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है।
- कुछ वस्तुओं पर, दर 20 प्रतिशत या 38 रुपए प्रतिवर्ग मीटर होगी जो कपिहले की तुलना में बहुत अधिक है।

### केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of indirect Taxes and Custom-CBIC)

- केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) वतित मंत्रालय के अंतरगत कारयरत राजस्व वभिग का एक भाग है।
- इस बोर्ड का मुख्य कार्य उगाही (शुल्क-संग्रह) से संबंधित नीतियों का करयान्वयन करना, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमा-शुल्क की उगाही करना एवं तसकरी से संबंधित गतविधियों को रोकना है।
- वर्तमान में इसके अध्यक्ष एस रमेश हैं। [2]
- आयातित उत्पाद जो महेंगे हुए हैं उनमें बुने हुए कपडे, पोशाक, ट्राउज़र, सूट और बच्चों के वस्त्र शामिल हैं।
- बांग्लादेश जैसे अल्प-वकिसति देशों की भारतीय बाज़ारों में पहुँच शुल्क मुक्त रहेगी।
- WTO मानदंडों के मुताबिक, भारत कपड़ा कषेत्र को और प्रोत्साहन नहीं दे पाएगा तथा सरकार ने घरेलू वनिरिमाण को प्रोत्साहति करने के लयि आयात शुल्क में वृद्धि की है।
- उल्लेखनीय है कि जून में धागा, कपड़ा और इनसे बने सामानों के आयात में 8.58% की करदिधि के साथ यह 168.64 मिलियन डॉलर हो गया। हालाँकि सूती धागे, कपड़े और इनसे बने सामानों का नरियात 24% बढ़कर 986.2 मिलियन डॉलर हो गया। मानव नरिमति सूत, कपड़े और इनसे बने सामानों का नरियात 8.45% बढ़कर 403.4 मिलियन डॉलर हो गया।

### कपड़ा उत्पाद पर सीमा-शुल्क बढ़ने से लाभ

- कुछ तैयार वस्त्र उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ने से भारतीय कपड़ा नरिमाण के लयि लागत का फायदा होगा।
- कई वदिशी कंपनयिँ घरेलू मांग को पूरा करने के लयि भारत में वनिरिमाण पर वचिर कर सकती हैं।
- यह घरेलू वनिरिमाण को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
- वशिषज्जों का मानना है कि इससे 'मेक इन इंडिया' को भी बढ़ावा मलैगा।